/font>

Title: Need to take concrete steps to mitigate the problem of unemployment in the country.

श्री भेरूलाल मीणा (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके पहले भी इस विाय को उठा चुका हूं लेकिन सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के कारण पुन : यह मामला उठा रहा हूं।

भारत सरकार ने जब से आर्थिक उदारीकरण के अंतर्गत अभी तक जितने भी सरकारी उपक्रमों का विनिवेश किया है तथा कर्मचारियों को वीआरएस दिया या छंटनी की है उससे देश में बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है। नव जवानों को शिक्षित होने के बावजूद भी रोजगार नहीं मिल रहा है। विनिवेश किये गये उपक्रमों में प्रबंधन की मर्जी से भर्तियां की जा रही हैं जिस कारण पूरे देश में अराजकता का वातावरण उत्पन्न होता जा रहा है और आम लोगों को आसानी से काम नहीं मिल पा रहा है। जो कर्मचारी विनिवेश के बाद कार्यरत हैं उन्हें भी नये प्रबंधन द्वारा परेशान करके नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। निजी उद्यमी केवल अपने मुनाफे के लिये उद्योगों का उपयोग कर रहे हैं उन्हें देश तथा उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की कोई चिन्ता नहीं है। मैं एक श्रमिक प्रतिनिधि होने के नाते पूरी जिम्मेदारी से सरकार का ध्यान आकर्ति कर रहा हूं कि विनिवेश के बावजूद भी श्रमिक अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। इसलिये इन कम्पनियों में सरकारी हस्तक्षेप एवं निगरानी होना आवश्यक है। अत: मेरी भारत सरकार से मांग है कि उक्त सभी तथ्यों को गम्भीरतापूर्वक लिया जाये तथा बेरोजगारी दूर करने के लिये शीघ्र उपाय किये जाये।